(2)

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

मंत्रिपरिषद् के लिए संलेख

विषय:– विकसित बिहार के लिये सात निश्चय के तहत् सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

वर्त्तमान राज्य सरकार का "न्याय के साथ विकास" के नजरिया को ध्यान मे रखते हुए राज्य के सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का मूल उद्देश्य राज्य का सर्वांगीण विकास है।

विकसित बिहार के लिये राज्य सरकार की ओर से सात निम्नांकित निश्चय (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–673 दिनांक 21.12.2015 की छाया प्रति संलग्न) किये गये हैं:–

1. **आर्थिक हल, युवाओं को बल**
2. **आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार**
3. **हर घर बिजली लगातार**
4. **हर घर नल का जल**
5. **घर तक, पक्की गली–नालियाँ**
6. **शौचालय निर्माण, घर का सम्मान**
7. **अवसर बढ़े, आगे पढ़ें**

उक्त सात निश्चयों में सूचना प्रावैधिकी विभाग को भी समाहित किया गया है, जिसमें प्रथम निश्चय आर्थिक हल, युवाओं को बल के अंतर्गत सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा **"राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।"**

विदित हो कि वर्त्तमान परिवेश में राज्य सरकार ने ई.–गवर्नेंस की अपार सम्भावनाओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के शिक्षित युवाओं को इससे अवगत कराने का संकल्प लिया है।

राज्य के युवाओं को ई.–गवर्नेंस से जोड़ना है तो इसके लिये यह आवश्यक है कि इन शिक्षित युवाओं को इन्टरनेट से जोड़ा जाय, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रम बदलाव एवं विकास से अवगत हो सकें।

राज्य के शिक्षित युवा यदि इन्टरनेट से टेक्नोफ्रेण्डली हो जाते हैं तो हमारी युवा शक्ति राज्य के विकास में बढ़–चढ़कर भाग लेगी, जिसका गुणोत्तर परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकती है।

2. उक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का निश्चय लिया है, जो कि सात निश्चयों में से एक है।

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना का क्रियान्वयन आगामी पाँच निम्नांकित वित्तीय वर्षों में किया जाना है :–

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Name of Plan	Financial Year 2016-17	Financial Year 2017-18	Financial Year 2018-19	Financial Year 2019-20	Financial Year 2020-21
1.	Free Wi-Fi in 267 Colleges + 14 University Campuses	10500.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00

3. योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ होगा, तथा कुल पाँच कार्यान्वित वर्षों के लिये ₹ 1,85,00,00,000.00 (एक सौ पचासी करोड़) मात्र (छाया प्रति संलग्न) का प्रस्तावित योजना एवं विकास विभाग के द्वारा निर्धारित कराते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

कृपया .....दें/-

Scanned by CamScanner

4. इस योजना का क्रियान्वयन वित्त विभाग के द्वारा प्रदत्त व्यय शीर्ष मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–07–दूर–संचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लघु शीर्ष–202–इलेक्ट्रॉनिक, मांग संख्या–25, उपशीर्ष –0113–निश्चय–विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में निःशुल्क वाई फाई, विपत्र कोड–P2852072020113, विषय शीर्ष–28 01–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये उपबंधित राशि ₹ 1,05,00,00,000.00 (एक अरब पाँच करोड़) मात्र से किया जायेगा।

5. योजना का क्रियान्वयन खुली निविदा के आधार पर स्टेट नोडल एजेन्सी बेल्ट्रॉन के द्वारा किया जायेगा।

6. योजना से संबंधित मुख्य विशेषताएँ निम्नांकित हैं:–

- Project with five years warranty.
- Ten indoor Wi-Fi hotspots in the college campus and 30 in university campus.
- Five outdoor Wi-Fi hotspots in the college campus and 10 in university campus.
- 10Mbps dedicated interent bandwidth in each campus.
- Secured Network.
- Connectivity to Students, Teaching and Non-Teaching Staffs.
- One resident engineer for three years in each university for required technical support and maintenance.

7. उक्त के साथ–साथ Free Wi-Fi हेतु आवश्यक रोडमैप निम्न रूप में किये जाने का प्रस्ताव है:–

Estimated fund requirement for one College Campus for three years project	₹ 65,00,000/-	Estimated fund requirement for one University Campus for three years project	₹ 1,05,00,000/-
Year		2016-17	
Number of University Campuses to be covered		14	
Number of Constituent College Campuses to be Covered		262	
Estimated fund requirement for the university campuses		₹ 14,70,00,000.00	
Estimated fund requirement for the constituent College Campuses		₹ 1,70,30,00,000.00	
Total fund santion required for the project		**₹ 1,85,00,00,000.00**	

8. वर्णित स्थिति में विकसित बिहार के लिये सात निश्चय के तहत् सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव है।

9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

10. योजना प्राधिकृत समिति की सहमति प्राप्त है। (योजना एवं विकास विभाग का ज्ञापांक–79 / यो.प्रा दिनांक 05.02.2016 की छाया प्रति संलग्न)।

11. संलेख की कंडिका–8 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 06 / सू० प्रा०–04 / 2016-132(अनु०) पटना, दिनांक 08.02.16.

प्रतिलिपि : संलेख की 45 प्रति (अनु० सहित) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ ए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक में सम्मिलित करने की कृपा की जाय।

अनु०– यथोक्त।

सरकार के सचिव

राजन्
05.02.16

...06-IT-04-16

Scanned by CamScanner

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

संचिका संख्या– 06-सू0प्रा0-04/2016

ज्ञापांकः 79/गो0प्रा0/यो0वि0, पटना, दिनांक 05-02- 2016

प्रतिलिपिः मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/मंत्री, सूचना प्रविधिकी विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक 2/2/16

ज्ञापांकः 79/गो0प्रा0/यो0वि0, पटना, दिनांक 05-02- 2016

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रविधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक 2/2/16

Scanned by CamScanner

दिनांक 05.02.2016 को मध्याह्न 12.00 बजे विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की कार्यवाही

योजना का नाम : विकसित बिहार के लिये सात निश्चय के तहत् सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव है।

विषय : वर्त्तमान राज्य सरकार का "न्याय के साथ विकास" के नजरियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का मूल उद्देश्य राज्य का सर्वांगीण विकास है।

विकसित बिहार के लिये राज्य सरकार की ओर से सात निम्नांकित निश्चय किये गये हैं:–

1. **आर्थिक हल, युवाओं को बल**
2. **आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार**
3. **हर घर बिजली लगातार**
4. **हर घर नल का जल**
5. **घर तक, पक्की गली–नालियाँ**
6. **शौचालय निर्माण, घर का सम्मान**
7. **अवसर बढ़े, आगे पढ़ें**

उक्त सात निश्चयों में सूचना प्रावैधिकी विभाग को भी समाहित किया गया है, जिसमें प्रथम निश्चय आर्थिक हल, युवाओं को बल के अंतर्गत सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा **"राज्य के सभी विश्वविद्यालयों" एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।"**

विदित हो कि वर्त्तमान परिवेश में राज्य सरकार ने ई.–गवर्नेंस की अपार सम्भावनाओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के शिक्षित युवाओं को इससे अवगत कराने का संकल्प लिया है।

राज्य के युवाओं को ई.–गवर्नेंस से जोड़ना है तो इसके लिये यह आवश्यक है कि इन शिक्षित युवाओं को इन्टरनेट से जोड़ा जाय, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रम बदलाव एवं विकास से अवगत हो सकें।

राज्य के शिक्षित युवा यदि इन्टरनेट से टेक्नोफ्रेण्डली हो जाते हैं तो हमारी युवा शक्ति राज्य के विकास में बढ़–चढ़कर भाग लेगी, जिसका गुणोत्तर परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं।

2. उक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का निश्चय लिया है, जो कि सात निश्चयों में से एक है।

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना का क्रियान्वयन आगामी पाँच निम्नांकित वित्तीय वर्षों में किया जाना है:–

क्रमशः 2/–

Scanned by CamScanner

5

Sl. No.	Name of Plan	Financial Year 2016-17	Financial Year 2017-18	Financial Year 2018-19	Financial Year 2019-20	Financial Year 2020-21
						(₹ in Lakh)
1.	Free Wi-Fi in 267 Colleges + 14 University Campuses	10500.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00

3. सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इनटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने से संबंधित व्यय शीर्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 में वित्त विभाग के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

चूंकि योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ होगा, इसलिये कुल पाँच कर्णांकित वर्षों के लिये ₹ 1,85,00,00,000.00 (एक अरब पचासी करोड़) मात्र का उद्व्यय योजना एवं विकास विभाग के द्वारा निर्धारित कराते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये वित्त विभाग के द्वारा बजटीय उपबंध भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

4. योजना से संबंधित मुख्य विशेषताएँ निम्नांकित हैं:–

- Project with five years warranty.
- Ten indoor Wi-Fi hotspots in the college campus and 30 in university campus.
- Five outdoor Wi-Fi hotspots in the college campus and 10 in university campus.
- 10Mbps dedicated interent bandwidth in each campus.
- Secured Network.
- Connectivity to Students, Teaching and Non-Teaching Staffs.
- One resident engineer for three years in each university for required technical support and maintenance.

5. उक्त के साथ–साथ Free Wi-Fi हेतु आवश्यक रोडमैप निम्न् रूप में किये जाने का प्रस्ताव है :–

Estimated fund requirement for one College Campus for three years project	₹ 65,00,000/-	Estimated fund requirement for one University Campus for three years project	₹ 1,05,00,000/-
Year		2016-17	
Number of University Campuses to be covered		14	
Number of Constituent College Campuses to be Covered		262	
Estimated fund requirement for the university campuses		₹ 14,70,00,000.00	
Estimated fund requirement for the constituent CollegeCampuses		₹ 1,70,30,00,000.00	
Total fund santion required for the project		₹ 1,85,00,00,000.00	

3. प्रस्ताव : विकसित बिहार के लिये सात निश्चय के तहत् सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव है।

क्रमशः 3/--

Scanned by CamScanner

6

4.	योजना का क्रियान्वयन	:	खुली निविदा के आधार पर योजना का क्रियान्वयन स्टेट नोडल एजेन्सी बेल्ट्रॉन के द्वारा किया जायेगा।
5.	संचिका संख्या–	:	06–सू०प्रा०–04 / 2016
6.	संलेख का ज्ञापांक एवं तिथि	:	ज्ञापांक–115 दिनांक 04.02.2016
7.	बजट शीर्ष एवं बजट उपलब्धता	:	इस योजना का क्रियान्वयन वित्त विभाग के द्वारा प्रदत्त व्यय शीर्ष मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–07–दूर–संचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लघु शीर्ष–202–इलेक्ट्रॉनिक, मांग संख्या–25, उपशीर्ष–0113–निश्चय–विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में निःशुल्क वाई फाई, विपत्र कोड–P2852072020113, विषय शीर्ष–28 01–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये राशि ₹ 1,05,00,00,000.00 (एक अरब पाँच करोड़) मात्र से किया जायेगा।
8.	समिति द्वारा लिया कंडिकावार निर्णय / यदि कोई हो तो – प्रस्ताव स्वीकृत / अस्वीकृत	:	अनुशंसित।

(राहुल सिंह)
सचिव
सूचना प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

(एच० आर० श्रीनिवास)
प्रधान सचिव (संसाधन)
वित्त विभाग, बिहार, पटना

(डॉ० दीपक प्रसाद)
प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

(शिशिर सिन्हा)
विकास आयुक्त,
बिहार, पटना

Scanned by CamScanner

पत्रांकः–07–सू०प्रा०–21/2015 76 7

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सरकार के सचिव

सेवा में,

श्री मोहन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 25-01-2016

विषयः– दिनांक–27.01.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य सरकार के सात निश्चयों के आकलन पर समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–270 दिनांक–15.01.2016 के आलोक में कहना है कि दिनांक–27.01.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के 7 (सात) निश्चयों के आकलन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के आलोक में पूर्व में विभागीय पत्रांक–64 दिनांक–20.01.2016 के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रपत्र सहित आपको उपलब्ध कराया गया था, उसमें आंशिक संशोधन किया गया है।

'उक्त संशोधन से संबंधित सामग्री प्रपत्र में अद्यतन रूप में भर कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

अनु०–यथोक्त।

Scanned by CamScanner

State Government's 7 Point Agenda

To set up free Wi-Fi facility at all State Government Universities and Constituent Colleges

Department of IT, GoB

Scanned by CamScanner

Requirements of Funds for Major Priorities

Rs. in

Sl. No.	Name of the Schemes	Number of Sectors	Concerned Department	Source of Funding	Fund Requirement					
					2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Tota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Setting up of Wi-Fi in all Colleges.	262 Constituent Colleges + 14 University Campuses	Information Technology	CPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CSS (CS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CSS (SS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EAP (World Bank/ADB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EAP (CS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EAP (SS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RIDF (NABARD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RIDF (SS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				14th Finance Commission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				State Plan	10500.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
				Total	**10500.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**	**18500.0**

Note :-

Setting up of Wi-Fi in all Constituent Colleges and University campuses shall be done. This shall cover a period of Five Years a commence from the Financial Year 2016-17.

(Rahul Singh)
Secretary to Government
Information Technology Department
Govt. of Bihar

Scanned by CamScanner